



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 472) पटना, सोमवार, 28 मई 2018

सं० प्र010ए/गृ0नि0अ0(विविध)—890/98—3830/वि0(अ0),
वित्त विभाग

संकल्प
24 मई 2018

विषय:— राज्य सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिमों की अधिसीमा में उत्क्रमण एवं सूद की दर में संशोधन तथा कम्प्यूटर अग्रिम की अधिसीमा में अभिवृद्धि/संशोधन।

राज्य सरकार के सेवी वर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम से संबंधित विभागीय संकल्पों/आदेशों में निम्नलिखित संशोधन किया जाना है :—

(क) गृह निर्माण अग्रिम :—

- (1) वित्त विभागीय संकल्प सं०-420 दिनांक 21.01.2000 की कंडिका-5 (i) एवं 809 दिनांक 22.05.2006 की कंडिका-(क) में यथा संशोधित आदेश सं०-626 दिनांक 30.06.2010 की कंडिका-(क) में वर्णित पे-बैंड में प्राप्त वेतन एवं ग्रेड-पे का 34 गुणा था, के स्थान पर 34 माह के मूल वेतन और अधिकतम 25.00 लाख रुपये अथवा घर/प्लेट की अनुमानित लागत या कर्मचारी के भुगतान क्षमता के अनुसार परिकलित राशि—इनमें से जो भी कम होगी, देय होगा। जहाँ तक प्रस्तावित भवन निर्माण/प्लेट क्रय की अधिकतम लागत का प्रश्न है, जो पूर्व में यह संबंधित कर्मों के पे-बैंड में प्राप्त वेतन एवं ग्रेड-पे का 134 गुणा के स्थान पर कर्मों के मूल वेतन के 139 गुणा हो सकती है परन्तु इसकी अधिकतम लागत सीमा एक करोड़ रुपये तक होगी।
- (2) इसी संकल्प की कंडिका-5 (ii), 809 दिनांक 22.05.2006 की कंडिका-(क) एवं आदेश सं०-887 दिनांक 26.05.2006 में यथा संशोधित आदेश सं०-626 दिनांक 30.06.2010 की कंडिका-(क) में वर्णित मौजूदा मकान के विस्तार/वृहद्दीकरण के लिए अधिकतम अनुमान्य राशि पे-बैंड में प्राप्त वेतन एवं ग्रेड-पे का 34 गुणा, के स्थान पर 34 माह के मूल वेतन के

आधार पर आकलित किया जाएगा, जो अधिकतम 10.00 लाख रुपये अथवा वृहद्दीकरण की लागत अथवा भुगतान क्षमता—इनमें से जो भी कम होगी, देय होगा।

- (3) इसी संकल्प की कंडिका-7 में अंकित सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम राशि की गणना करने के लिए, अग्रिम अदायगी की क्षतमा केन्द्र के अनुरूप निम्नानुसार परिकलित की जाएगी।

(क) 20 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 40%
(ख) 10 वर्ष के बाद परन्तु 20 वर्ष के पहले सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 40%, मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान का 65% समायोजित किया जाएगा।
(ग) 10 वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 50%, मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान का 75% समायोजित किया जाएगा।

- (4) सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम हेतु देय अग्रिम की राशि पर वित्त विभागीय आदेश सं0-898 दिनांक 08.08.2003 में अंकित सूद की दरों के स्थान पर केन्द्र के अनुरूप सूद की दर 8.5% होगी। अग्रिम के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों के अनुपालन एवं सक्षम पदाधिकारियों द्वारा मूलधन की पूरी राशि का ससमय भुगतान का प्रमाण-पत्र नहीं देने पर निर्धारित सूद की दर के अतिरिक्त 2.5% सूद चार्ज किया जाएगा।
- (5) उपर्युक्त संकल्प/आदेश की अन्य शर्त यथावत रहेंगी।

(ख) कम्प्यूटर अग्रिम :-

- (1) वित्त विभागीय संकल्प सं0-1624 दिनांक 29.08.2002 की कंडिका-2, संकल्प सं0-1497 दिनांक 15.11.2007 की कंडिका-(ख)(i), आदेश सं0-626 दिनांक 30.06.2010 की कंडिका-(घ), 1478 दिनांक 07.12.2010 में संशोधनोपरान्त केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मियों को कम्प्यूटर अग्रिम 50.00 हजार रुपये एवं पूरे सेवा काल में 5 बार देय होगा।
- (2) उपर्युक्त संकल्प/आदेश की अन्य शर्त एवं उनपर देय सूद की दर और संबंधित बिन्दुओं के बारे में पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया/नियम लागू रहेंगी।

(ग) मोटरकार अग्रिम एवं मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम ।—राज्य सरकार के सेवी वर्ग को दी जानेवाली मोटरकार/मोटरसाईकिल/स्कूटर/ मोपेड अग्रिम एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दी जानेवाली मोटरकार अग्रिम समाप्त किया जाता है।

(घ) उल्लिखित अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 472-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>